भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमो में निम्न विषयो का समावेश

- ग्रामीण क्षेत्रो में आधारभूत सुविधाओ जैसे सकुल, स्वास्थ्य सुविधा सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण आदि का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि उत्पादकता में सुधार।
- सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सेवाओ जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान
- कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए योजनाओ को लागू करना
- ऋण और सब्सिडी के माध्यम से उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबीरेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगत परिवारो और स्वय सहायता समूह (एस एचजी) के लिए सहायता।

→ ग्रामीण विकास कार्यक्रम निम्नलिखित है:-

(1) सामुदायिक विकासपरियोजना →

भारत में ग्रामीण विकास के लिए यह आवश्यक था कि कृषि की दशाओ में सुधार किया जाये, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदला जाये, आवास की दशाओं में सुधार किया जाये, किसानो को कृषि योग्य भूमि प्रदान कीजाये। जन-स्वास्थ्य तथा शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाये। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सन 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलो

Scanned with CamScanner

2 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना :-

प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सितम्बर 2016 में (1985) इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। यह एक लोक कल्याणकारी योजना है इस योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ लोगों को आवास देने का उद्देश्य रखा गया है इसमें जिन के लोगों के पास पहले से पक्का मकान नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए कम ब्याज दर आर्थिक मदद दी जाती है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :- (फरवरी 2009)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1986 में हुई उस समय इसका नाम राष्ट्रीय पेयजल मिशन था। इसका उद्देश्य सभी परिवारों को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के लिए उपयोग और प्रयोग किया है सुनिश्चित करे। सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी कार्यात्मक शौचालयों मूत्रालयों और सुरक्षित पीने के पानी के लिए पहुँच सुनिश्चित अपने खुद के पीने के पानी के स्रोतों और उनके गांवों में स्वच्छता के प्रबंधन के लिए पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के लिए अनुकूल वातावरण और समर्थन प्रदान करते है।

PAGE NO.
DATE

प्राय: सभी क्षेत्र-विशेष कार्यक्रमों को एकीकृत कर वाटरशेड
विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन
व्यावहारिक रूप में 1995-96 में प्रारम्भ होगा। लेकिन वर्ष 1994-95
को इस कार्यक्रम के लिये तैयारी का वर्ष निहित किया गया है
इस अवधि में परियोजना का चयन, कार्यान्वयन, एजेंसी का
चयन, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार का कार्य
सम्पादित होगा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य है:-
1 मिट्टी, फसल, घास एवं वृक्षों के अधिकाधिक उत्पादन के लिये
जल एवं वनस्पति का समुचित प्रबंध,
2 मिट्टी तथा जल का संरक्षण, मिट्टी क्षरण और उसके बहाव पर रोक
या कमी लाना, 3 बहते हुए जल में अवसाद कम करना तथा
4 कौन सा कार्य, कब कैसे और किसके द्वारा होगा यह सुनिश्चित
करना।

7. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :-

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पिछली जवाहर रोजगार योजना के विशाल सम्पादन, अच्छी तरह से संगठित तथा पुनर्व्यवस्थित है इस योजना को 1 अप्रैल 1999 को आरम्भ किया गया। इस योजना के तहत यह ग्रामीण निर्धनों के जीवनकाल की उत्तमता में बेहतर सुधार के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभदायक रोजगार मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- इस योजना के तहत एससी तथा एसटी नागरिकों के लिए फंड का 22.5 %. निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के तहत 3%. सालाना आवंटन का इस्तेमाल विकलांगों के लिए बाधा रहित बुनियादी ढांचे की रचना के लिए किया जाएगा।
- इस योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा सालाना काम को

Scanned with CamScanner

11. अन्त्योदय अन्न योजना :-

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक केंद्रित तथा गरीब आबादी के अत्यन्त गरीब वर्ग तक पहुंचने के लिए "अन्त्योदय अन्न योजना" को दिसम्बर 2000 में शुरू किया गया था। अन्त्योदय अन्न योजना राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली बीपीएल परिवारों में से अत्यन्त गरीब परिवारों की पहचान करके उन्हें रियायती दर पर यानी 2 रु प्रति किलो गेहूं और 3 रु प्रति किलो चावल उपलब्ध कराती है।

12. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :-

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितम्बर 2001 को प्रारम्भ हो गई। यह कार्यक्रम पहले स्वर्ण जयन्ती रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोखिम पूर्ण आवासों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि इस योजना के तहत रोजगार देने में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता जहां एनआरईपी प्रारम्भ हो चुका है।

13. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना :-

यह योजना 2000-01 में

PAGE NO.	
DATE	

दिया गया है। इस अंतरित योजना के लिए निधियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य योजना को जारी की जाती है तथा राज्यों के पास लाभभोगियों को चुनने तथा इसके कार्यान्वयन को चुनने के लिए अपेक्षित अनुमति है। राज्य सरकारों को अनाज बीपी एल दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना =)

भारत सरकार ने 25 सितम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों मे 500 या इससे अधिक आबादी वाले (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों मे 250 लोगों की आबादी वाले गांव) सड़क-संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त से ही इसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है।

इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गांवों को होगा, जहां छोटे किसान शहरों से सीधे जुड़ सकेंगे और अपनी फसलें बेच पाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे सड़कों की सही रखना यानि अगर किसी तरह की परेशानी से सड़क खराब होती है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। इसमे सरकार ने 'मेरी सड़क' के नाम से एक सरकारी ऐप जारी किया है। अगर आपके गाव की सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है या फिर किसी कारण खराब हो गई तो आप इस ऐप के जरिए सीधे प्रधानमंत्री से शिकायत कर सकते है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के कुछ अवसर सृजित होते है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रेल क्रासिंग और तिराहों पर ओवर ब्रिज बनाने का काम भी शामिल है।

Scanned with CamScanner

• विशेष रूप से गाँवों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित क...

16. भारत निर्माण योजना :-

'गांव की ओर एक कदम' की नीति स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार ने 16 दिसम्बर 2005 को 'भारत निर्माण योजना' नाम की एक नई योजना की शुरुआत... इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का वि... करना है। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालि... किया जा रहा है। इस योजना को लागू करने की अवधि चा... साल के लिए निर्धारित की गयी है। जिसका अनुमानित व्यय... 174000 करोड़ रुपये का है। यह मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केन्द्रि... जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ... ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल है।

17. ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम :-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि... आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उ... से 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य नि... है:- 1. बाल मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना।
2. महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जल, शौचालय व स्वच्छता प्रतिरक्षण एवं पोषाहार जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
3. स्थानीय स्थानिक बिमारी के साथ संचरणीय एवं गैर संचरणीय बी... की रोकथाम एवं नियंत्रण। 4. एकीकृत वृहद प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाना। 5. जनसंख्या स्थिरीकरण एवं लैंगि... तथा जनसांख्यिकी सन्तुलन।
6. स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना

Teacher's Signature

तैयार करने का एकमात्र अधिकार है तथा ग्राम सभा के अप्रूवल से इसका कार्यान्वियन है ⊙ इस योजना के तहत इस प्रोग्राम में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच 25 : 75 % खर्च की साझेदारी के आधार पर केन्द्र आयोजित योजना के रूप में जारी किया जायेगा।

8. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ⇒

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में पहली अप्रैल, 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं-सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे रह रहे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें कोई भी पेन्शन न मिल रही हो, उन्हें अन्न सुरक्षा प्रदान करवाई

9. अन्नपूर्णा योजना ⇒

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत 2000-2001 में की गई। 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के दरिद्र वरिष्ठ नागरिक जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए हकदार हैं लेकिन उन्हें यह पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है उन्हें इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज की मुफ्त आपूर्ति इस योजना के अन्तर्गत की जाती है।

वर्ष 2002-2003 से इस राज्य योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल हैं के साथ राज्य योजना में अंतरित कर

प्रारम्भ हुई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भारत सरकार की
ही महत्वपूर्ण योजना है उसके अन्तर्गत गांव के विकास के
आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा
विभिन्न सहयोग किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित का
चलाये जाते हैं:-
मिड डे मील योजना
1. समेकित बाल विकास योजना
2. किशोरी शक्ति योजना
3.

1. मिड डे मील योजना :)

यह योजना विद्यालय के बच्चों के
सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। सर्वप्रथम मि
मील योजना को 15 अगस्त 1995 को 2000 से आदि
प्रोजेक्ट के स्कूलों में लागू किया गया था। इस योजना की सफ
सिद्ध होने के बाद इस स्कीम को साल 2004 में पूरे देश
के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया था और वर्तमान में य
स्कीम हमारे पूरे देश के सरकारी स्कूलों में चल रही है।

2. समेकित बाल विकास योजना :)

समेकित बाल विकास योजना 6
तक के सभी बच्चे, गर्भवती महिलायें एवं धात्री माताओं के
पोषण एवं स्वास्थिक सेवाओं का एकीकृत समावेश कर उनके
को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत देश में चलाय
है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास
ज्यादा सहयोग मिल रहा है।

Scanned with CamScanner

Neel Kamal
PAGE NO.
DATE / /

(11 अक्टूबर 2014)

23. सांसद आदर्श ग्राम योजना :-

11 अक्टूबर 2014 को प्रारम्भ की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों और यहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वंय के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बनें। यह योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक गांव की पहचान करें और 2016 तक एक आदर्श गांव का विकास करें। और 2019 तक दो और गांवों को शामिल करते हुए देश भर में फैले 6 लाख गांवों में से 2,500 से अधिक गांवों को इस योजना का हिस्सा बनाएं। इसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं में सुधार, उच्च उत्पादकता, मानव विकास में वृद्धि करना, आजीविका के बेहतर अवसर, अधिकारों व हक की प्राप्ति, व्यापक सामाजिक गतिशीलता और समृद्ध सामाजिक पूंजी प्राप्त करना।

24. प्रधानमंत्री जन धन योजना :- प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारम्भ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ई-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को कहा। योजना के

Teacher's Signature

Scanned with CamScanner

ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्याएं :-

ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्याएं निम्नलिखित है।

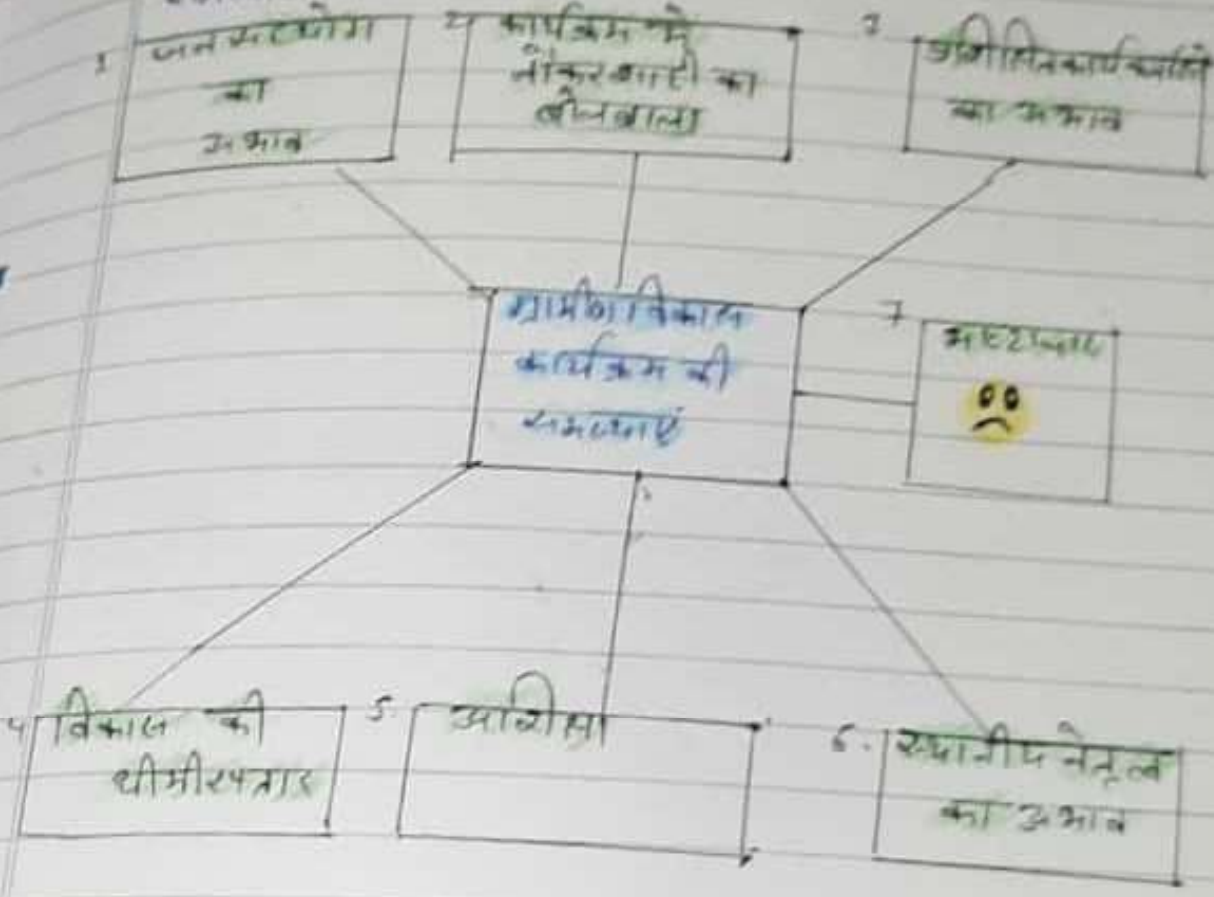

जन सहयोग का अभाव :-

विकास कार्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर जनसहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रत्येक स्तर पर इसका नितान्त अभाव है। यहा लोगो मे जागरूकता नही होने के कारण कार्यक्रम पूर्णरूप से प्रभावी नही बन पाते। यहा पर जो लोग सामाजिक व आर्थिक स्थिति वाले ही इस कार्यक्रम को जान पाते है। गाव के अन्य लोगो मे सहयोग का पूर्ण अभाव पाया जाता है।

Teacher's Signature _____

Scanned with CamScanner

2. कार्यक्रम में नौकरशाही का बोलबाला :- विकास योजना के प्रत्येक स्तर पर नौकरशाही का बोलबाला रहा है। योजना के उच्च पदस्थ अधिकारी निम्न अधिकारीयो का आदेश तो देते रहे लेकिन अपने नीचे ग्रामीण स्तर के अधिकारीयों की अनुभवसिद्ध तथा विश्वस्त बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो सके। इसके फलस्वरूप यह योजना ग्राम सेवक जिस पर इस योजना की सफलता आधारित है वे गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों की चाटुकारी करने में लग गए

3. प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव :- कार्यक्रमो के विकास के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का अभाव पाया जाता है। यद्यपि सरकार ने कुछ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों तथा विशेष शिविरों का आयोजन किया लेकिन वह व्यवस्था की अपर्याप्त थी कि जिस तेजी से विकास खण्डो की संख्या में वृद्धि रही है, उतनी तेजी से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी, कार्यकर्त्ता तथा कर्मचारी अपने दायित्व को समुचित रूप से निर्वाह नहीं कर सकते।

4. विकास की धीमी रफ्तार :- जो गाँव, शहरों के किनारे या मुख्य राजमार्गों पर बसे है उनका विकास तो हो गया है परन्तु जो गाँव शहरी सीमा से दूर है वे अभी भी विकास की राह देख रहे है। कई गाँवों को तो अब तक मुख्य

Scanned with CamScanner

सड़को से जोड़ा भी नही गया है। नेता और राजनीतिक पार्टियाँ केवल चुनाव के समय इन गावों की ओर रुख करती है और ग्रामवासियो के मन में नयी आस दे जाते हैं।

5. अशिक्षा :-

अशिक्षा ग्रामीण विकास कार्यक्रमो की सबसे बड़ी समस्या है लोगो को इन कार्यक्रमो के बारे मे कोई जानकारी नही होती है। अशिक्षा के कारण वे अपने अधिकारो व दायित्वों के प्रति सजग ही नही होते।

6. स्थानीय नेतृत्व का अभाव :-

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय नेतृत्व का विकास करना है लेकिन आरम्भ से ही उस ओर अधिक ध्यान नही दिया गया। वास्तव मे ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक - आर्थिक असमानता जातिगत भिन्नताओ तथा उच्च जातियो के शोषण के कारण निर्धारित प्रकार किये बिना स्वस्थ नेतृत्व को विकसित करना सम्भव नही है।

7. भ्रष्टाचार :-

हमारे पास दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। गंगा-यमुना के मैदान मे इतना अनाज पैदा किया जा सकता है कि पुरे देश का पेट भरा जा सकता है। इन्ही विशेषताओं के कारण दुसरे देश आज भी हमारी ओर ललचाई नजरो से देखते हैं लेकि हमारी गिनती भ्रष्ट देशों में होती है। हमारी तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। केन्द्र सरकार अथवा विश्व बैंक की कोई भी योजना हो। उसके इरादे कितने ही महान क्यो न हो